शकरपुर में महिला से लूट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, प्रमोद पर पहले से दर्ज हैं 26 केस

पूर्वी दिल्ली। शकरपुर इलाके में सात अगस्त की रात को बीच गली में पीछे से गला दबाकर महिला से चेन व कुंडल लूटने वाले तीन बदमाशों को पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की पहचान मयूर विहार थाने के घोषित बदमाश व त्रिलोकपुरी निवासी प्रमोद उर्फ देव उर्फ चिकना, इसके साथी नितिन व नजफगढ़ निवासी अंगद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। प्रमोद पर पहले से लूट, झपटमारी के 26 केस दर्ज हैं। 30 जून 2025 को ही प्रमोद जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस ने तीनों बदमाशों पर संगठित अपराध की धारा लगाई है। जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि सात अगस्त की रात साढ़े दस बजे रश्मि जैन नाम की महिला से स्कूटी सवार बदमाशों ने गला दबाकर लूट की थी।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 201 ● नई दिल्ली ● सोमवार 11 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

उपराष्ट्रपति चुनावः साझा उम्मीदवार उतारने के लिए विपक्ष ने कसी कमर; साथी दलों से संपर्क करने में जुटे खरगे

नई दिल्ली ।उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्षी गठबंधन का साझा उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम तलाशने और आम सहमति बनाने के लिए गठबंधन के सहयोगी दलों से संपर्क कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का मानना है कि वे चुनाव में अपने दमदार प्रदर्शन के जरिये सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव नौ सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सत्तारूढ़ गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने पर चर्चा शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श के लिए इंडिया ब्लॉक के साझेदारों के बीच बातचीत चल रही है। जबकि खरगे आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क

कर रहे हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टियों के बीच आम सहमति है कि इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगा। विपक्षी खेमे के एक वर्ग का मानना है कि भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही इंडिया गठबंधन को अपना उम्मीदवार तय करना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 9 सितंबर को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के त्यागपत्र में कहा गया, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच एकता बढ़ी है। विपक्षी गठबंधन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित चुनाव धांधली के खिलाफ एकजुट है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की डिनर पार्टी में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब खरगे सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल की ओर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बढ़त हासिल है। 543 सदस्यीय लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच रिक्तियां हैं। राज्यसभा की पांच रिक्तियों में से चार जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से है। पंजाब की यह सीट पिछले महीने हुए उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 782 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

दिल्ली यूनिवर्सिटी : डूसू चुनाव के नियमों में सख्ती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली ।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल छात्र संघ चुनावों में अनुशासन और नियमों को लेकर पहले से ज्यादा कड़ा रुख अपनाने का ऐलान किया है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि डीयू की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, विजयी जुलूस में ढोल-नगाड़े और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है. पिछले चुनाव में प्रचार के दौरान विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुचाने और तोड़फोड़ की घटनाओं के चलते कई बार मतगणना रोकनी पड़ी थी. इन घटनाओं को देखते हुए इस बार प्रशासन ने शुरुआत से ही स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम

निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार न तो विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और न ही दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए नामांकन के समय ही सभी प्रत्याशियों को एक लाख रुपये का बांड भरना होगा. ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ चुनाव से अयोग्यता तक की कार्रवाई हो सकती है. साथ ही, शक्ति प्रदर्शन करने, प्रचार में ढोल, लाउडस्पीकर, पोस्टर आदि के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. हालांकि, प्रचार के लिए विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों और विभागों में 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' की व्यवस्था करेगा, जहां उम्मीदवार अपने विचार और घोषणाएं साझा कर सकेंगे. इस बार इन दीवारों का आकार भी पहले से बड़ा होगा, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले.

बहस और भाषण को मिलेगा बढ़ावा

चुनाव में स्वस्थ बहस को बढ़ावा देने के लिए सभी कॉलेज, विभाग और केंद्र उम्मीदवारों के लिए डिबेट और भाषण जैसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे.

इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों को सीधे अपने मुद्दे रखने का अवसर मिलेगा. निर्देशों के पालन के लिए विश्वविद्यालय ने 2 विशेष समितियां बनाई हैं.

एक कॉलेज स्तर पर और दूसरी विश्वविद्यालय स्तर पर. ये समितियां चुनाव के दौरान नियमों के अनुपालन पर नजर रखेंगी. इस संदर्भ में एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिससे छात्रों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी मिल सकेगी.

दिल्ली के चाणक्यपुरी में थार गाड़ी ने दो लोगों को कुचला, एक की मौत, नींद में था ड्राइवर

नई दिल्ली । दिल्ली के चाणक्यपुरी थाना के पॉश इलाके में रविवार (10 अगस्त) सुबह बड़ा हादसा हुआ. राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर थार गाड़ी ने एक शख्स को कुचल दिया. कार की चपेट में आए व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद सड़क पर घंटों तक लाश पड़ी रही.

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक, थार गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था? यह एक हादसा था या हत्या की सोची-समझी साजिश? सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.थार गाड़ी से शराब की बोतलें मिली हैं. फोरेंसिक टीम से पूरे वाहन की जांच कराई जा रही है. चाणक्यपुरी थाना पुलिस के अनुसार, 11 मूर्ति के पास एक तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि थार का आगे का पहिया तक अलग हो गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी थार ड्राइवर 26 साल का युवक है जिसको मौके से ही पकड़ लिया गया है. उसने अपने दोस्त की थार ली थी. पूछताछ में उसने बताया है कि उसकी आंख लग गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया. हालांकि, पुलिस जांच कर रही है कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं. आरोपी ड्राइवर की गाड़ी का बीते एक अगस्त को ओवर स्पीडिंग के चलते चालान भी कटा हुआ था. गाड़ी की जांच में पुलिस ने पाया कि गाड़ी पर 2 हजार रुपये का चालान है, जिसे अभी भरा नहीं गया है. बता दें, सफेद रंग की थार में केवल चालक मौजूद था और वाहन का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का होने की जानकारी मिली है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, पुलिस साक्ष्य जुटाने के साथ गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और घटना के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. ऐसा ही हादसा कुछ समय पहले जोधपुर में देखा गया था. जोधपुर शहर के बालसमंद क्षेत्र स्थित रॉयल्टी नाका चौराहे पर, बुधवार (6 अगस्त) को एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने 2 महिलाओं को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में, एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर भड़के पूर्व राजदूत; कहा- जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रही कांग्रेस

नई दिल्ली । ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस पर पूर्व राजदूत ने नाराजगी जाहिर की है। पूर्व राजदूत केबी फैबियन ने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रही है। वह चीजों को गहराई से समझ नहीं रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व राजनयिक केबी फैबियन ने कहा कि वायुसेना प्रमुख का बयान हमें आश्वस्त करने वाला है। मगर अब कुछ लोग रणनीति, ग्रे ज़ोन या अन्य क्षेत्रों के गहन ज्ञान के बजाय सामान्य ज्ञान पर भरोसा करते हुए फिर से पूछेंगे कि यह सब कब हुआ? युद्ध तीन महीने पहले 10 मई को समाप्त हो गया था। हमें अब क्यों बताया जा रहा है? वायुसेना प्रमुख या सेना प्रमुख को हमें ये बातें बताने से किसने रोका था? उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कांग्रेस जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रही है। यह संघर्ष पीओके को आजाद कराने के लिए नहीं था। हमारा मकसद आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बुनियादी ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक करना था। फिर पाकिस्तान हम पर हमला करके अपनी हरकतें बढ़ाएगा। फिर हमने इतनी जोरदार जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान अमेरिका जाकर रो पड़ा। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कह रहे हैं; यह कूटनीतिक नहीं है। एक सरकार का मुखिया दूसरे सरकार के मुखिया को झूठा नहीं कह सकता। पूर्व राजदूत ने कहा कि एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत बेहतर कर सकता था, वो यह कि जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने युद्धविराम की मांग की, तो भारत तुरंत बयान दे सकता था कि पाकिस्तान ने युद्धविराम की मांग की है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। भारतीय डीजीएमओ को भारतीय नेतृत्व से सलाह-मशविरा करके हां और ना में जवाब देना चाहिए था। बंगलूरू में आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के दौरान एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छह लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था। उन्होंने इसे भारत द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मारने का रिकॉर्ड बताया। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि कम से कम पांच लड़ाकू विमान और एक बड़ा विमान, जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या कोई अन्य हो सकता है, को करीब 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमारे सैनिकों की क्षमता का प्रमाण है।

दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव पर सियासत तेज, आप ने बीजेपी और एलजी पर बोला हमला

नई दिल्ली । दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद हो रहे जलभराव से न केवल आम जनता की परेशानी बढ़ गयी है, बल्कि इस कारण राजधानी का सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है. सीवर और डिसिल्टिंग कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं. जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और रेखा सरकार पर हमलावर तेवर अपना रखा है. एक ओर आम आदमी पार्टी बीजेपी और उपराज्यपाल पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार को अव्यवस्था और कुप्रबंधन का जिम्मेदार ठहरा रही है. वहीं, बारिश के बाद हुए हादसों और मौतों ने इस आरोप-प्रत्यारोप की जंग को और तेज कर दिया है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी की सड़कों को तालाब में बदल दिया है. राखी के दिन कई बहनें घंटों तक सड़कों पर फंसी रहीं, जबकि जलभराव और ढही दीवारों के कारण सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो बच्चे, तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे. वहीं, एक दर्दनाक घटना में ढाई साल का बच्चा अपने घर से बाहर निकलते समय सीवर में गिर गया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई.

बीजेपी की डिसिल्टिंग दावे पर सवाल

भारद्वाज ने बीजेपी और उपराज्यपाल

पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद डिसिल्टिंग का कोई ठोस असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा. उन्होंने बताया कि पिछले साल से ही रू और तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार-बार पत्र लिखकर थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्रालय को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी इस पर चुप्पी साधे रखा.

भारद्वाज का दावा दस्तावेज हो रहे गायब

आप नेता ने दावा किया कि, डिसिल्टिंग ऑडिट के निर्देशों पर कार्रवाई को लेकर जब उन्होंने ऋद्ध दाखिल की, तो मुख्य सचिव के दफ्तर से जवाब मिला कि उनके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है. यह साबित करता है कि सरकारी रिकॉर्ड को गायब किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है और जनता के पैसे का हिसाब देने से बच रही है.

बीजेपी सांसद के निरीक्षण दौरे पर भारद्वाज ने कसा तंज

वहीं, भारद्वाज ने भारी जलभराव के अगले दिन बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के जलभराव निरीक्षण दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा, उन्हें एक घड़ी दे दीजिए, ताकि पता चल सके कि वे किस टाइम जोन में जी रहे हैं. जलभराव कल हुआ, बच्चे कल मरे और वे आज निरीक्षण करने निकले हैं.

उन्होंने कहा कि निरीक्षण का सही समय बारिश के दौरान होता है, न कि तब जब पानी निकल चुका हो. बीजेपी नेताओं और दिल्ली सरकार का यह रवैया केवल दिखावा है. पिछली बार भी बारिश के बाद रेखा गुप्ता निरीक्षण करने गई थीं, जब पानी पहले ही निकल चुका था.

ईडी और चुनाव आयोग दोनों की विश्वसनीयता संकट में

अनिल जैन

पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार का राजनीतिक औजार बन चुके प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट में अक्सर तल्ख टिप्पणियां सुनाई देती है। अब सरकार ने संसद में सवालों के जवाब में इसके कामकाज का जो ब्योरा दिया है वह भी कम दिलचस्प नहीं है। वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा को बताया गया है कि 2015 से 2025 तक यानी पिछले 10 साल में ईडी ने 5,892 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें सिर्फ 15 लोगों को सजा हो पाई है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इस अवधि में ईडी ने 49 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सरकार ने बड़े गर्व से बताया है कि ईडी ने नया कानून बनने के बाद से लेकर मार्च 2014 तक सिर्फ 1883 मुकदमे दर्ज किए थे। यानी हर साल औसतन 200 मामले दर्ज हुए, जबकि उसके बाद के 10 साल में हर साल औसतन 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। यह आंकड़ा पहले आया हुआ है कि जिन राजनीतिक लोगों के खिलाफ ईडी ने मुकदमे दर्ज किए उनमें 95 फीसदी विपक्षी पार्टियों के नेता है। सरकार ने यह नहीं बताया है कि जिन लोगों के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है वे कौन लोग है, लेकिन यह जगजाहिर तथ्य है कि उनमें ज्यादातर वे लोग है जो भाजपा में शामिल हो चुके है। बहरहाल ईडी की इसी कार्यप्रणाली पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा है, आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते। आपको कानून के दायरे में रह कर काम करना होगा।

महाराष्ट्र में फिर चुनाव फिक्सिंग का इरादा

लगता है कि चाहे वो मुख्य चुनाव आयोग हो या राज्य चुनाव आयोग सबने तय कर लिया है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि सुधरे और चुनाव में निष्पक्षता कायम रहे। इस समय मुख्य चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मैच फिक्सिंग के साथ ही वोट चोरी करने जैसे आरोप लग रहे है कि इस बीच महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। राज्य चुनाव कार्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान तो ईवीएम से होगा लेकिन ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें नहीं लगाई जाएंगी।

इसका मतलब है कि मतदान के बाद कोई पर्ची नहीं निकलेगी और मतदाता यह नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट किसको गया। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कई प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोटिंग होगी इसलिए वीवीपैट मशीनें नहीं लगाई जा सकती है। ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे है, अन्यथा सरकार तो किसी न किसी बहाने चुनाव टाल ही रही थी। ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीनों को अनिवार्य बनाया है और पैडम मशीनों की पर्चियों का मिलान ईवीएम के साथ करने का आदेश भी दिया गया है। इसलिए समय की कमी या कोई और बहाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग बताना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिन में इस पर विवाद बढ़ेगा। विपक्षी पार्टियां बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि बिना वीवीपैट मशीन के चुनाव हो।

उत्तराखंड में भाजपा को झटका

उत्तराखंड में पांच साल पर सत्ता बदलने की परंपरा के उलट पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर इतिहास बनाया। लेकिन दूसरी बार जीतने के बाद से ही पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है, जो इस बार स्थानीय निकाय चुनावों में दिखी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय जीते है, जिन पर दोनों पार्टियां दावा कर रही है। लेकिन असलियत यह है कि लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बावजूद भाजपा को झटका लगा है। भाजपा परोक्ष रूप से जिला पंचायत की 358 में से 320 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से 120 से कम सीट जीत पाई। यही नहीं, उसके जितने भी दिग्गज है उनके परिवार के सदस्य भी चुनाव हार गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के जिले चमोली में कुल 26 जिला पंचायत सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवार सिर्फ चार जीत पाए। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को सात सीटें मिलीं। चमोली में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी और लैंसडाउन में भाजपा विधायक महंत दिलीप की पत्नी चुनाव हार गईं। चमोली जिले में भाजपा के जिला अध्यक्ष गजपाल बर्थवाल चौथे स्थान पर रहे। सल्ट में भाजपा विधायक महेश जीना का बेटा और नैनीताल की भाजपा विधायक सरिता आर्य का बेटा भी चुनाव हार गया। नैनीताल की निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष व भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया चुनाव हार गईं। लाखों फॉलोवर और सब्सक्राइबर वाली इन्फ्लूएंसर दीपा नेगी भी भाजपा से चुनाव लड़ी थीं, जिनको सिर्फ 256 वोट मिले।

तमिल नेताओं का बिहार विरोध

तमिलनाडु के नेताओं का बिहार विरोध समझ से परे है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में मतदाता बनाने के खिलाफ चेन्नई से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के वित्त व गृह मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने इस मुद्दे पर विस्तार से सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है। उन्होंने तमिलनाडु में सवा छह लाख बिहारी मतदाता जोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए लिखा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके कामकाज की जगह पर क्यों मतदाता बनाया जा रहा है। चिदंबरम चाहते है कि मजदूर वोट डालने अपने गांव जाएं। उन्होंने लिखा है कि छठ पर्व मनाने के लिए मजदूर बिहार जाएंगे, तो वे वहां वोट भी डाल दें। सवाल है कि अगर छठ के समय चुनाव नहीं हो तो मजदूर क्या करें और क्या छठ के समय सारे मजदूर बिहार चले जाते है? चिदंबरम ने अपने बिहार, हिंदी या उत्तर भारत के विरोध में यह भी नहीं देखा कि तमिलनाडु के कितने लोग तमिलनाडु के बाहर दूसरे राज्यों में मतदाता है। भले ही बिहार में नहीं है लेकिन दिल्ली में तो बड़ी संख्या में तमिल लोग मतदाता है। उनकी अपनी बस्ती है और वे वहीं वोट डालते है। इसी तरह मुंबई में भी तमिलों की बड़ी आबादी है, जो वहां मतदाता है। तो क्या यह कहा जाए कि दिल्ली, मुंबई के तमिल लोग वोट डालने अपने प्रदेश क्यों नहीं चले जाते। बिहार के चुनाव से पहले चिदंबरम जैसे नेता कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे है।

भाजपा को ईसाई मतदाताओं की फिक्र

केरल में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भाजपा को उम्मीद है कि इस बार उसका प्रदर्शन ऐतिहासिक हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था। पार्टी का खाता भी खुला था और दो सीटों पर उसने कांटे की लड़ाई बना दी थी। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में भाजपा राज्य के ईसाई मतदाताओं को पटाने में लगी है। लेकिन इस बीच मामला बिगड़ गया छत्तीसगढ़ में, जहां दो ईसाई महिलाओं को धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों केरल से थीं और तीन आदिवासी महिलाएं किसी कार्यक्रम में जा रही थीं, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को लेकर बड़ा विवाद हुआ। वाम दलों के साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया तो भाजपा की ओर से ऐसे मौम्प और कार्टून बने, जिनमें सोनिया और राहुल गांधी को चर्च के आगे नतमस्तक दिखाया गया। लेकिन जल्दी ही केरल भाजपा ने मुद्दा अपने हाथ में ले लिया क्योंकि दोनों नन केरल की रहने वाली थीं। केरल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर दिया और कहा कि जल्दी ही दोनों ननों को जमानत मिलेगी। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार भी खूब चला। फिर दोनों ननों को जमानत भी मिल गई। सबसे दिलचस्प तमाशा यह था कि केरल के भाजपा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर खुद छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। दोनों ननों का स्वागत कर उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि भाजपा ने उनकी जमानत कराई है।

कैशलेस इंडिया की कहानी: यूपीआई ने रचा नया इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की ओर से हाल ही में जारी किए गए एक नोट, बढ़ता रिटेल डिजिटल भुगतानः इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व के अनुसार, भारत तेज भुगतान में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इस बदलाव का मूल आधार एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, जिसे यूपीआई के नाम से जाना जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने देश में लोगों के पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को बदल दिया है। आज, भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने 18 बिलियन से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं। यूपीआई अब केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है। यह सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे में नवाचार के लिए एक वैश्विक मानक है। आज यूपीआई का स्तर उल्लेखनीय है। अकेले जून 2025 में, इसने 24.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान किए। इसके जरिए 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन किए गए। बीते साल इसी महीने 13.88 बिलियन लेन-देन की तुलना में हुई यह प्रगति स्पष्ट है। केवल एक साल में इसमें लगभग 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई प्रणाली अब 491 मिलियन लोगों और 65 मिलियन कारोबारियों को सेवाएं देती है। यह 675 बैंकों को एक ही मंच पर जोड़ती है, जिससे लोग बिना किसी चिंता के आसानी से भुगतान कर सकते हैं कि वे किस बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के डिजिटल भुगतान का दायरा अभूतपूर्व वृद्धि के साथ पूरी दुनिया में अग्रणी बन चुका है। पिछले छह वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक देश में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनकी कुल राशि 12,000 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस डिजिटल भुगतान की लहर ने विशेष रूप से वंचित एवं ग्रामीण समुदायों के वित्तीय लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-एनपीसीआई, फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर जैसी पिछड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करने के लिए 2021 में आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड- पीआईडीएफ की स्थापना की। अब तक इस फंड के माध्यम से लगभग 4.77 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट देशभर में तैनात किए जा चुके हैं। ये टच पॉइंट डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को छोटे से छोटे गांव, कस्बा, सरकारी दफ्तर और व्यापारी केंद्रों तक पहुंचाने में सहायक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की प्रगति को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी आरबीआईकृडीपीआइ विकसित किया है, जो हर छह महीने में प्रकाशित होता है। इसका आधार मार्च 2018 है, जब यह 100 था। सितंबर 2024 तक यह सूचकांक 465.33 तक पहुंच चुका था और मार्च 2025 तक 493.22 पर पहुंच गया, जो देश भर में डिजिटल भुगतान के अपनाने, बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन में निरंतर बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। यह संकेत है कि भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से सशक्त हो रहा है। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान कर दी है। यूपीआई की मदद से लाखों छोटे विक्रेता डिजिटल भुगतान स्वीकार कर पा रहे हैं, जिससे नकद लेनदेन की निर्भरता कम हो रही है। इसके अलावा, छोटे व्यापारियों के लिए कम-मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देना, टीआरईडीएस के माध्यम से छूट देने की व्यवस्था और डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दर को युक्तिसंगत बनाना जैसे कदम डिजिटल भुगतान को अधिक सुलभ और लाभकारी बना रहे हैं। पीआईडीएफ के अंतर्गत टियर-3 से लेकर टियर-6 नगरों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति के इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विकास किया गया है। इससे गांव और छोटे शहरों में भी डिजिटल भुगतान को अपनाने के रास्ते खुले हैं। डिजिटल टच पॉइंट्स के बढ़ते नेटवर्क ने इन इलाकों में भी आर्थिक लेनदेन की प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया है। यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम बना हुआ है। जून 2025 तक यूपीआई पर प्रतिदिन औसतन 613 मिलियन लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता और निर्बाध सुविधा का प्रमाण है। इसने देश को नकद मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम और पास पहुंचाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा डिजिटल भुगतान में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे साफ होता है कि डिजिटल भुगतान तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। आज, भारत में सभी डिजिटल लेन-देन में 85 प्रतिशत यूपीआई के माध्यम से होते हैं। इसका प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी है, और यह वैश्विक स्तर पर रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों के लगभग 50 प्रतिशत को संचालित करता है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं। ये भरोसे, सरलता और तेजी को दर्शाते हैं। हर महीने, अधिक से अधिक लोग और व्यवसाय अपने भुगतानों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बढ़ता इस्तेमाल इस बात का एक मजबूत संकेत है कि भारत तेजी से एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब दुनिया का नंबर एक रियल-टाइम भुगतान सिस्टम भी बन गया है। इसने रोजाना ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग में वीजा को पीछे छोड़ते हुए बढ़त हासिल कर ली है। वीजा के 63 करोड़ 90 लाख ट्रांजेक्शन के मुकाबले यूपीआई हर दिन 64 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन संभालता है। यह पैमाना असाधारण है, खासकर जब आप यह देखते हैं कि यूपीआई ने यह उपलब्धि केवल नौ वर्षों में हासिल की है। अब दुनिया भर में लगभग 50 प्रतिशत ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से होते है। यह गति और आसानी के लिए बनाई गई एक खुली और अंतर-संचालनीय प्रणाली की शक्ति को दर्शाता है। इसकी सफलता की कहानी केवल घर तक ही सीमित नहीं है। यूपीआई की मौजूदगी सीमाओं के पार भी महसूस हो रही है। यह संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस समेत सात देशों में पहले से ही उपलब्ध है। फ्रांस में इसका प्रवेश एक मील का पत्थर है क्योंकि यह यूरोप में यूपीआई का पहला कदम है। इससे वहां यात्रा कर रहे या रहने वाले भारतीयों को विदेशी लेनदेन की सामान्य परेशानियों के बिना सहजता से भुगतान करने की सुविधा मिलती है। भारत यूपीआई को ब्रिक्स समूह में एक मानक बनाने के लिए भी प्रयास कर रहा है, जिसमें अब छः नए सदस्य देश भी शामिल हैं। अगर ऐसा होता है, तो इससे रेमिटेंस में सुधार होगा, वित्तीय समावेशन में तेजी आएगी और डिजिटल भुगतान में वैश्विक तकनीकी अग्रणी के तौर पर भारत की छवि मजबूत होगी।

डिजिटल भुगतान की इस तेजी के साथ भारत ने खुद को एक अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी के रूप में स्थापित कर लिया है। डिजिटल रुपया और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान नेटवर्क के विकास से वित्तीय लेनदेन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और त्वरित होंगे। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को और देश-विदेश में विस्तार देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारत एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हब बन सके। भारत का डिजिटल भुगतान सशक्तिकरण ने न केवल आर्थिक लेनदेन को सरल बनाया है, बल्कि गरीब और पिछड़े वर्गों को भी वित्तीय दुनिया का हिस्सा बनाया है। यह डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी है, जो रोजाना करोड़ों नागरिकों की जिंदगी में सुधार लाकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है।

सम्पादकीय...

ये रिश्ता क्या कहलाता है!

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोली। उसे काफी भला-बुरा कहा। और तो और ''वोट चोर'' तक कह दिया। पर चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला। उसकी तरफ से बोले भी तो सिर्फ सूत्र बोले। बेशक, सूत्र थोड़ा नहीं खूब बोले। और तो और ''वोट चोर'' की गाली के जवाब में, उतने ही जोर से ''माफी मांगो'' भी बोले--शपथ पत्र दो, नहीं तो माफी मांगो! फिर भी, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं। सूत्र तो जैसे अनदेखे प्रकट होते हैं, वैसे ही संदेश कारगर नहीं हो तो अनदेखे ही गायब भी हो जाते हैं। सूत्रों से आने वाला जवाब तो कोई जवाब नहीं है, बन्नू! जवाब वह है जो, सवाल चुनाव आयोग से होता है, तो जवाब आता है किरण रिजिजू और संबित पात्रा का यानी मोदी पार्टी का। देश जानना चाहता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है वैसे ऐसा रिश्ता अक्सर मियां-बीवी का होता है, वह भी पुराने मियां-बीवी का। बीवी से सवाल पूछो तो मियां जी खुद ब खुद जवाब देने लग जाते हैं। और मियां से कुछ कह दो तो बीवी नाराज हो जाती है, गरियाने पर उतर आती है। तो क्या यह वही रिश्ता है वैसे ऐसा मामला सहजीवन का भी हो सकता था, लेकिन वह मोदी पार्टी को मंजूर नहीं होगा। आखिरकार, संस्कारी पार्टी है। तो क्या यह रिश्ता बाकायदा जन्म-जन्मांतर वाला गठबंधन ही कहलाता है यानी साझा राज, साझा संपत्ति, साझा घर। होने को तो साझा सरनेम भी, मगर वह कंपल्सरी नहीं है बल्कि अब तो कुछ-कुछ आउट ऑफ फैशन सा हो चला है। और इस रिश्ते में पब्लिक कहां आती है। बिहार की पब्लिक इस समय खासतौर पर परेशान है, चुनाव आयोग और अपने रिश्ते को लेकर। सिद्धांत यह कहता है कि गठबंधन वाला रिश्ता होना तो वास्तव में पब्लिक और चुनाव आयोग का चाहिए। वह भी परंपरागत गठबंधन वाला। यानी पब्लिक का आसन ऊंचा और चुनाव आयोग का आसन उससे ठीक-ठाक नीचे। पर यह सिर्फ सिद्धांत कहता है। विरोधियों की मानें तो मोदी पार्टी, पब्लिक और चुनाव आयोग के गठबंधन को तुड़वाकर, चुनाव आयोग को ले उड़ी है और सिर्फ ले ही नहीं उड़ी है, उसके साथ बाकायदा घर बसाकर भी बैठ गयी है। बेशक, यह कोई यूं ही नहीं हो गया। इसके लिए मोदी पार्टी को काफी मेहनत भी करनी पड़ी है। बाकी चीजों के अलावा बाकायदा चुनाव आयोग का दिल जीतना पड़ा है। इसके लिए खासतौर पर चुनाव आयुक्तों के ही चयन का तरीका बदलना पड़ा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ा दी थी। उसका कहना था कि आयोग वही जो मोदी मन भाए, डैमोक्रेसी में नहीं चलेगा। ऐसा आयोग, पब्लिक और चुनाव आयोग के रिश्ते के लिए ठीक नहीं था। पर मोदी जी ने अपनी पार्टी और आयोग के रिश्ते के रास्ते की हरेक बाधा को ही मिटाने मन बना लिया था। कानून बनाकर, झटपट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने और चुनाव आयोग के बीच से हटा दिया। एक बार फिर इसका इंतजाम कर दिया कि चुनाव आयोग वही, जो मोदी मन भाए। अब बिहार में पब्लिक को पता चल रहा है, चुनाव आयोग से नाता टूटने का नतीजा। मोदी पार्टी की नयी-नयी वफादारी के चक्कर में आयोग ने पब्लिक के सिर पर सर की आफत डाल दी। 65 लाख पुराने वोटरों के नाम कट गए। और कटे भी ऐसे जैसे उनके नाम कभी लिस्ट में थे ही नहीं। अब जिसको नाम चाहिए, नये सिरे से वोटर के रूप में भर्ती के लिए पर्चा दाखिल करो, दस्तावेज लगाओ, तब अगर बड़े बाबू संतुष्ट हुए तो वोट का अधिकार मिल सकता है, वर्ना भूल जाओ! वोट देना कोई मौलिक अधिकार थोड़े ही है! और दूसरे करोड़ों के नाम दस्तावेज जमा न होने के चक्कर में अधर में अटक गए हैं। किस का वोट रहे और किस का कट जाए, कोई नहीं जानता। यह भी बड़े बाबू के रहमो-करम पर है, किस का क्या दस्तावेज जरूरी हो जाए और किस का क्या दस्तावेज काफी हो जाए, कोई नहीं जानता। और अब सुप्रीम कोर्ट के आगे चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है, जिन पैंसठ लाख के नाम कट गए, उनकी कोई सूची नहीं दी जाएगी। पब्लिक को ऐसी सूची मांगने-पाने का हक ही नहीं है। पब्लिक को यह जानने का भी हक नहीं है कि किस का नाम किसलिए काटा गया है। पब्लिक का ना जानकारी का हक और चुनाव आयोग का नहीं बताने का हक ही, सबसे ऊपर है। वैसे विपक्ष वाले नाहक चुनाव आयोग और मोदी पार्टी के रिश्ते को अवैध कहकर बदनाम करते हैं। इस रिश्ते का कम से कम यह मतलब नहीं है कि आयोग और विपक्षी पार्टियों का रिश्ता, दुश्मनी का ही रहेगा। राज करने वालों की जुगल-जोड़ी देखकर, विपक्ष का जलना भी तो कोई सही बात नहीं है। सच पूछिए तो चुनाव आयोग तो अब भी विपक्ष का भी उतना ही ख्याल रखता है, जितना किसी और का। विपक्ष वालों के मांगने पर, वे जिस मशीन से पढ़े जाने लायक रूप में वोटर लिस्ट चाहते हैं, उस रूप में अगर आयोग नहीं दे रहा है, तो क्यों जाहिर है कि इसीलिए कि विपक्षी पार्टियों के लोग, जो चुनाव नतीजे आ चुके, उन पर माथाफोड़ी में अपना टैम और इनर्जी बर्बाद नहीं करें। बिहार में भी, मसौदा सूची मशीन से पढ़े जाने वाले रूप में मुहैया कराने के हफ्ते भर बाद ही चुनाव आयोग ने अपनी गलती को सुधार लिया और मसौदा सूची को भी मशीन से पढ़ने का रास्ता बंद कर दिया आखिर क्यों मशीन के भरोसे विपक्षी तो विपक्षी, इक्का-दुक्का पत्रकार भी, इतने बड़े काम में तरह-तरह से खोट निकालने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे और कभी शून्य पते वाले वोटरों के बहाने, तो कभी एक-एक घर में दो-दो सौ वोटरों, एक-एक परिवार में चालीस-पचास सदस्यों के होने या मर चुके लोगों के नाम सूची में पहुंच जाने के बहाने, समाज में नेगेटिविटी फैला रहे थे। यह चुनाव आयोग से देखा नहीं गया। और जो विपक्ष के कहने पर मतदान के खास समय की वीडियो रिकार्डिंग नहीं देने बल्कि नष्ट करने की चुनाव आयोग ने ठान रखी है, तो आयोग के पिछले मुखिया राजीव कुमार पहले ही बता चुके थे, इस फुटेज को देखने में तो किसी को भी 273 साल लग जाएंगे। आयोग नहीं चाहता है कि पब्लिक का समय बेकार में ऐसी चीजों में बर्बाद हो। पब्लिक से चुनाव आयोग का रिश्ता भले ही एक्स यानी पूर्व का कहलाता हो, आयोग को अब भी पब्लिक की परवाह है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोक लहर के संपादक हैं।)

किसान हित सर्वोपरि

अगर गेहूं और धान के भारतीय बाजार को अमेरिकी कम्पनियों के लिए खोल दिया जाए तो भारतीय किसानों की हालत क्या होगी यह सब जानते है। अमेरिका भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गेहूं, कपास, मक्का, सोया, अमेरिकी मक्खन और दूध उत्पाद के लिए भारत का बाजार खोलने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत इन उत्पादों के लिए पहले ही आत्मनिर्भर है। दूसरा संवेदनशील पहलू यह भी है कि अमेरिकी पशुपालन में जानवरों को भी मांस खिलाते है। वे अधिक दूध के लिए गायों को भी मांसाहार परोसते है। भारत की एक बड़ी आबादी शाकाहारी है। अमेरिका के डेयरी उत्पाद उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। भारतीय किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए है और उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल लाखों भारत के छोटे किसानों की आजीविका का है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में 16 प्रतिशत योगदान देता है।

किसान मुद्दे भारत के लिए अति संवेदनशील है। भारत में अधिकतर लोगों का जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इसलिए भारत में किसान हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया और बाद में उसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। ट्रम्प भारत पर दबाव बढ़ाकर अपनी सभी मनमानी शर्तें मनवाना चाहते है लेकिन भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार महान कृषि वैज्ञानिक एन.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प की धमकियों का दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ''भारत अपने किसानों, पशु पालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है और मैं उनके कल्याण के लिए किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार हूं।'' यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील किसान हितों के मुद्दे पर ही अटकी हुई है। ट्रम्प दबाव बनाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू करने की तिथि भी 27 अगस्त रखी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भारत किसानों के मुद्दे पर अमेरिका से क्यों टकरा रहा है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, फल और बादाम-पिस्ते जैसे मेवों को बिना किसी शुल्क के भारतीय मार्केट में एंट्री मिले लेकिन भारत ने अब तक सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और सेब जैसे कुछ उत्पादों के लिए ही बाजार खोलने पर सहमति दी है। जबकि मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी जैसे सेक्टर्स के लिए भारत साफतौर से मना कर रहा है। इसके पीछे असली वजह यह है कि अमेरिका के अधिकतर मक्का और सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) होते है, जबकि भारत में अभी तक जीएम फसलों के आयात की इजाजत नहीं है। भारत में जीएम फसलों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है और खुद बीजेपी से जुड़े कई संगठन जीएम फसलों के विरोध में है। जीएम फसलों के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील में एक बड़ा टकराव का मुद्दा बने हुए है। भारत में डेयरी केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि करोड़ों छोटे और भूमिहीन किसानों की आय का साधन है। भारतीय किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए, बाजारों तथा उनकी जमीन पर कार्पोरेट नियंत्रण के खिलाफ लम्बा आंदोलन किया था। अमेरिका भारत को अपने माल का डंपिंग यार्ड बना देना चाहता है। अमेरिका में एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन की लागत 1700 रुपए है जबकि भारत सरकार द्वारा एक क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है। भारतीय किसानों के पास औसतन एक हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर गेहूं और धान के भारतीय बाजार को अमेरिकी कम्पनियों के लिए खोल दिया जाए तो भारतीय किसानों की हालत क्या होगी यह सब जानते है। अमेरिका भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गेहूं, कपास, मक्का, सोया, अमेरिकी मक्खन और दूध उत्पाद के लिए भारत का बाजार खोलने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत इन उत्पादों के लिए पहले ही आत्मनिर्भर है। दूसरा संवेदनशील पहलू यह भी है कि अमेरिकी पशुपालन में जानवरों को भी मांस खिलाते है। वे अधिक दूध के लिए गायों को भी मांसाहार परोसते है। भारत की एक बड़ी आबादी शाकाहारी है।

अमेरिका के डेयरी उत्पाद उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से मेल नहीं खाते। भारतीय किसान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए है और उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल लाखों भारत के छोटे किसानों की आजीविका का है। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में 16 प्रतिशत योगदान देता है। कोरोना महामारी के काल में अगर किसी सैक्टर ने भारत को बचाया है तो वह कृषि क्षेत्र ही रहा। महामारी के दिनों में भी कोई भारतीय भूखा नहीं सोया। ऐसे में किसान हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। हमें विश्व बाजार में भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, कृषि अनुसंधानों एवं खाद्य परसंस्करण पर ध्यान देना होगा। भारत को ऐसी मोर्चाबंदी करनी होगी जिससे कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार बढ़े और हम अमेरिका की चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य पैदा कर सकें।

कुत्तों का बढ़ता आतंक

दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है तथा कुत्तों के काटने से लोगों के दिलों में खौफ बढ़ रहा है। दिल्ली के अलावा देश के अनेक राज्यों के बड़े शहरों में कुत्तों के नागरिकों पर हमले से हुई मौतों के प्रति प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है, इस बात को लेकर लोग चिन्तित है। नोएडा की सोसायटी में स्कूली बच्चों पर कुत्तों का हमला हो या दिल्ली के पूठकला में एक 6 साल की बच्ची की कुत्ते के काटने से मौत का मामला हो या फिर बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की वारदातें हों, हालात अच्छे नहीं है जो प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे है। दिल्ली में बच्ची की कुत्ते से काटने से हुई मौत की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पिछले दिनों आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के बढ़ रहे मामलों पर एक अखबार की मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। पीठ ने बताया कि इस रिपोर्ट में कई चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में हर रोज कुत्तों के काटने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे रेबीज से होने वाली बीमारियों का शिकार बन रहे है। पीठ ने कहा है कि इस रिपोर्ट को प्रधान न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। सड़कों के दोनों ओर कुत्तों के झुंड वाहनों के पीछे भागते है तो दुर्घटनाएं भी हो रही है। कुत्तों के हमले से कोई बचे तो कैसे इसका समाधान भी खोजना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए दो बच्चों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दिल्ली के पूठकलां इलाके में पागल कुत्ते के काटने की वजह से एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई थी। कुत्ते के काटने के बाद वह रेबीज का शिकार हो गई, जिसके बाद इलाज शुरू होने के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका और 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस बच्ची के अलावा एक चार साल के छोटे बच्चे पर भी कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। रिपोर्ट में यह बताया गया कि बच्चों के परिवार वालों के बार-बार शिकायत करने पर कथित तौर पर स्थानीय अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया। जो लोग घरों में कुत्ते पालते है वे काफी हद तक उनसे आत्मीयता का भाव रखते हुए निभाते भी है लेकिन यदाकदा अंजान मेहमान या आगंतुक पर पालतू कुत्ते हमला भी कर देते है। पिछले दिनों भी 22 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में एनसीडीसी की एक रिपोर्ट को सामने रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आए है। केंद्रीय मंत्री एसपी. सिंह बघेल ने लिखित तौर पर जानकारी दी कि 2024 में कुत्तों के काटने के कुल 37,17,336 मामले सामने आए और रेबीज के कारण हुई संदिग्ध 54 मौतें दर्ज की गई। सचमुच यह चौंकाने वाला है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने तथा इसका विरोध करने वालों के मामले में भी दर्जनों केस हाईकोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे है। दिल्ली के अनेक इलाकों में आरडब्ल्यूए तथा कुत्ते के लवर ग्रुप के बीच झगड़े की खबरें भी विवादों के रूप में कोर्ट तक सुनवाई के दौर से गुजर रही है। लोग घरों के पास कुत्तों के जमा होकर बसेरे बना लेने के खिलाफ जब शिकायत करते है तो एमसीडी दस्ता उन्हें पकड़ने आता है तो डॉग लवर्स ग्रुप और अन्य संरक्षक संस्थानों के बीच जंग छिड़ जाती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैफलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। [illegible]

विधान सभा अध्यक्ष ने विधान सभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने विधान सभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। आज यहां विधान भवन में आहूत एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही सदन चलता है। सकारात्मक वातावरण में तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का परिदृश्य देश और दुनिया में बदला है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा व सहयोग से विधान सभा में नवाचार किए जा रहे हैं। 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेन्ट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कल 11 अगस्त, 2025 से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2025 के द्वितीय सत्र का शुभारम्भ होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रदेश के समग्र विकास की धुरी है। विगत वर्षों में विधान सभा ने पूरे देश में संसदीय कार्य प्रणाली की नजीर प्रस्तुत की है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सदन स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा के लिए जाना जा रहा है। यह कार्य दलीय नेताओं के सहयोग से सम्भव हुआ है। विधान सभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विधान सभा में नवाचार की श्रृंखला शुरू हुई है। सदन में डिजिटाइजेशन, गैलरी के म्यूरीकरण, हॉल के नवीनीकरण जैसे विभिन्न कार्य किये गये हैं। यह कार्य देश के लिए अनुकरणीय बने हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री आदि सम्मानितजन इन नवाचारों को देखने आते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री जी ने सत्र के सुचारु संचालन में सत्ता पक्ष के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गम्भीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अपने सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। विधान सभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि

प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण एवं सतत विकास को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस सत्र में सदस्यगण 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेन्ट की कार्ययोजना के सम्बन्ध में आगामी 13 अगस्त से 24 घण्टे के लिए सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएं। यह सार्थक परिचर्चा देश व प्रदेश की प्रगति का माध्यम बनेगी और उत्तर प्रदेश विधान सभा देश में राज्य की एक नई छवि प्रस्तुत कर पाएगी। यह किसी पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि राज्य का एजेण्डा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस विजन डॉक्यूमेन्ट को आगामी तीन माह में तैयार करने का है। राज्य सरकार 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डॉक्यूमेन्ट को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का कार्य करेगी। विजन डॉक्यूमेन्ट के दृष्टिगत आम जनता के विचारों को जानने के लिए क्यू0आर0 कोड जारी किया जा रहा है। यह क्यू0आर0 कोड विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए जाएंगे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने विधान भवन के प्रवेश द्वार के नवीनीकृत गुम्बद और नवीनीकृत अतिविशिष्ट जलपान गृह एवं विधान सभा के नवीनीकृत सभा मण्डप तथा नवीनीकृत सभाकक्ष संख्या 15 का लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से ही सदन को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। सभी दलों ने सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। यह एक अच्छी परम्परा है। सदस्यगण सदन में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों को रखते हैं, लेकिन इस विजन डॉक्यूमेन्ट के माध्यम से वह पूरे प्रदेश के समग्र विकास की बात रख सकेंगे। इस अवसर पर मत्स्य मंत्री श्री संजय निषाद भी उपस्थित थे। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के श्री माता प्रसाद पाण्डेय, अपना दल (सोनेलाल) के श्री राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की श्रीमती मिथिलेश पाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के श्री ओम प्रकाश राजभर, निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल के श्री रमेश सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के श्री रघुराज प्रताप सिंह तथा बहुजन समाज पार्टी के श्री उमाशंकर सिंह ने अपने-अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 10 अगस्त, 2025 को उनकेसरकारी आवास पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने शिष्टाचार भेंट की।

मंदिर-मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर दी जा रही आपदा को दावत, मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान

मुरादाबाद।

मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी. हसन ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और दरगाहों पर बुलडोजर चलाकर हमने ईश्वर को नाराज कर दिया है। यही नाराजगी प्राकृतिक आपदाओं को न्योता दे रही है। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा भी इसी का परिणाम लगती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का ईको सिस्टम लगातार नष्ट किया जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इन प्रदेशों में दूसरे मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। पूर्व सांसद ने कहा, कि ईश्वर, अल्लाह और वाहे गुरु में कोई फर्क नहीं है। जिन इबादतगाहों को तोड़ा जा रहा है, वे सब उसी के हैं। वहां सभी धर्मों के लोग अपने-अपने तरीके से इबादत करते हैं। मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज और गुरुद्वारे में अपने रीति-रिवाज के अनुसार अरदास। परेशानी के समय लोग इन्हीं स्थानों पर माथा टेकते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन कहा कि कुछ लोग भूल गए हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो इंसान कहीं से भी खुद को नहीं बचा पाता। इसलिए अगर इबादतगाहें अवैध रूप से बनी भी हैं, तो उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उन्हें खाली करा

लेना चाहिए। डॉक्टर हसन ने यह टिप्पणी उत्तराखंड के धराली में आई आपदा से जोड़कर की, जिस पर इंटरनेट मीडिया में बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर, बुलडोजर से मंदिर-मस्जिद गिराए जाने से नाराज है। उनके बयान पर यूपी की सियासत गरमा गई। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस पर डॉक्टर एसटी. हसन ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को कुछ लोगों ने तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर खोजे जा रहे बुखार के मरीज, अब तक 1017 मिले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी फीवर ट्रैकिंग कैंप और घर-घर क्लोरीन टैबलेट वितरण का कार्य करा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और पार्षदों के समन्वय से फीवर एवं मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को कुल दस कैंप लगाए गए। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दस्तक अभियान की तर्ज पर घर-घर जाकर बुखार के मरीजों की सूची तैयार की गई। आज कैंप में 167 बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू की जांच की गई, जिसमें कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। सभी मरीजों को दवाएं दी गईं। अब तक कुल 1017 बुखार के मरीजों की जांच हो चुकी है।

सैफनी में सिपाही के घर छह लाख की चोरी, रिपोर्ट दर्ज

सैफनी।

नगर के बड़ी मस्जिद मोहल्ले में शनिवार रात अज्ञात चोर सिपाही के घर को निशाना बनाकर खिड़की के सहारे दो मंजिला मकान के कमरे में घुस गए। चोर मौका पाकर नगदी और जेवरात समेत करीब छह लाख रुपए के माल को समेट कर फरार हो गए। आँख खुली तो बिखरे पड़ा समान देखकर चोरी का पता लगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नगर के बड़ी मस्जिद मोहल्ला निवासी मोहम्मद इदरीश पुत्र शकूर यूपी पुलिस में सिपाही हैं। इन दिनों वह अमरोहा जिले में तैनात हैं। शनिवार को भी वह अपने कार्यस्थल पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि घर पर उनके परिजन दुमजले पर बरामदे में सोए हुए थे। करीब एक बजे के बाद अज्ञात चोर कमरे के पीछे से खिड़की खोलकर कमरे में घुस गए। अलमारी में रखे साढ़े चार तोले सोने व 350 ग्राम चांदी के कीमती आभूषण, दो लाख 80 हजार रुपये की नगदी सहित करीब छह लाख रुपए के माल को समेट कर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि रात को पौने दो बजे के समय जब उनके बेटे की आंख खुली तो अलमारी खुली हुई थी और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। जिसके बाद घर में चोरी होने का पता लगा, जिससे उनके होश उड़ गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। गृह स्वामी सिपाही मोहम्मद इदरीश ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में विवेचना की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई होगी।

जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं

जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है लेकिन पुलिस उनको रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों भी चोर सैफनी में एक घर को निशाना बनाकर नकदी और जेवर ले गए थे। अब चोरों ने पुलिस के घर को ही निशाना बना लिया। इससे लगता है कि पुलिस रात को गश्त नहीं कर रही है।

बरसात में आसमानी कहर...छत गिरने से मलबे में दबकर महिला की मौत

संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव में बरसात के दौरान मकान की छत गिर जाने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है। त्योहार के दिन दिए हुए हादसे के बाद घर में मातम पसरा है। शनिवार रात को बरसात के दौरान शकरपुर सोत गांव में 65 वर्षीय मनसुख के परिवार के बाकी लोग घर के बाहर वाले कमरे में बैठे बातें कर रहे थे जबकि मनसुख व उसकी पत्नी हरप्यारी अंदर वाले कमरे में थे। रात लगभग 9 बजे अचानक मकान की छत गिर गए तो बाहरी कमरे में बैठे परिवार के लोग बाहर आ गये। हरप्यारी व मनसुख मलबे के नीचे दब गये। परिवार के लोगों ने मदद के लिए शोर मचाया तो गांव के लोग आ गये। ग्रामीणों और परिजनों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबे मनसुख व हरप्यारी को बाहर निकाला। दोनों को गंभीर हालत में संभल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से गंभीर हालत में दोनों को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान हरप्यारी की मौत हो गई। जबकि मनसुख की हालत नाजुक बनी हुई है।पुलिस ने पंचनामा भरकर हरप्यारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

'गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, सबूत हो तो सदन में लाओ', बीजेपी मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी बीएसपी विधायक को खुली चुनौती

बलिया ।

उत्तर प्रदेश के बलिया में कटहल नाले पर बने नए पुल के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को दयाशंकर सिंह ने विधायक उमाशंकर पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वह ÷गीदड़ भभकी÷ से डरने वाले नहीं हैं।

पोल खोल दी तो मंत्री भाग खड़े होंगे

विवाद की शुरुआत 5 जुलाई को हुई थी, जब एनएच-31 पर पीडब्ल्यूडी द्वारा देर रात बिना किसी पूर्व सूचना के पुल चालू कर दिया गया। इस पर मंत्री दयाशंकर ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम उमाशंकर सिंह के इशारे पर उठाया गया। उधर, उमाशंकर सिंह ने जवाबी हमला करते हुए मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने की बात कही थी और कहा था कि अगर उन्होंने दयाशंकर की ÷पोल खोल÷ दी तो

मंत्री भाग खड़े होंगे। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर उमाशंकर के पास भ्रष्टाचार से जुड़े कोई साक्ष्य हैं तो उन्हें विधानसभा में पेश करें, ना कि केवल मीडिया में बयानबाजी करें।

ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण पत्र मिला या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पुल के उद्घाटन से नहीं, बिना एनएचएआई की मंजूरी और उचित प्रक्रिया के पालन के बिना इसे चालू किए जाने पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि पुल पर अभी तार लटके हुए थे और ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण पत्र मिला या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बिहार की पुल गिरने की घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा जोखिम को लेकर चिंता जताई। यह मुद्दा अब विकास कार्यों से हटकर राजनीतिक टकराव में बदल गया है। स्थानीय जनता इसे वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देख रही है। अब सबकी नजरें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां उमाशंकर सिंह यदि अपने दावों को लेकर साक्ष्य पेश करते हैं, तो यह मामला नया मोड़ ले सकता है।

लालकिले की सुरक्षा में फिर सेंध, विस्फोटक लेकर घुसा डमी आतंकी; दहशतगर्द ने सेल्फी ली और बनाई वीडियो

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल लालकिले की सुरक्षा में फिर एक बार सेंध लग गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का डमी आतंकी विस्फोटक लेकर घुस गया। वह उस जगह पर पहुंच गया जहां, प्रधानमंत्री के भाषण के समय ज्ञानपथ पर बच्चे बैठते हैं। इतना ही नहीं डमी आतंकी ने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों के बीच में सेल्फी भी ली और वीडियो भी बनाई। पिछली बार की तरह इस बार भी लालकिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी डमी आतंकी को पकड़ नहीं पाए। इससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। जोन के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव का कहना है कि उनको डमी आतंकी के लालकिले में घुसने के बारे में जानकारी नहीं है। लालकिले में डमी आतंकी के घुसने की तीसरी घटना है। पिछली बार की तरह इस बार भी डमी आतंकी पकड़ में नहीं आया। दिल्ली पुलिस के एक विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली है कि ये डमी आतंकी निषाद राज रोड से पेट्रोल पंप के पास दीवार फांदकर अंदर गया था यहां पर दीवार के पास कोई सुरक्षा व पेट्रोलिंग नहीं थी। दीवार को लेकर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इसके बाद डमी आतंकी सिक्योरिटी एरिया में घुस गया था। इसके बाद वह मिंटिंग एंक्लोजर के पास ज्ञानपथ के पास पहुंच गया। बताया जा रहा है कि उसने वहां देर वहां मौज मस्ती भी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डमी आतंकी शुक्रवार शाम को लालकिले पर गया था और वहां रात आठ बजे तक रहा। स्पेशल सेल ने जब इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह व अन्य सीनियर अधिकारियों को भेजी तब इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि डमी आतंकी की सेल्फी व वीडियो भी पुलिस आयुक्त को भेजी गई है। इस घटना से उत्तरी जिला पुलिस व प्रधानमंत्री सिक्योरिटी यूनिट के पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

देर शाम तक नहीं हुई थी कार्रवाई

पिछले सप्ताह जब दो डमी आतंकी लालकिले के अंदर गए और पकड़े नहीं गए थे तो लालकिले की सुरक्षा में तैनात सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। इस बार लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की सूचना नहीं मिली थी। नार्दर्न रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने इस बाबत मोबाइल जवाब देते हुए कहा कि डमी आतंकी बता कर जाते हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल सेल के पुलिसकर्मी सुरक्षा को चेक करने के लिए डमी आतंकी भेजते थे। उनसे जब लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बता कर गया था इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। जब पूर्व में लापरवाही पर सात पुलिसकर्मियों के निलंबन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले डमी आतंकी बता कर नहीं गए थे। ऐसे उनके दोनों बयानों में विरोधाभास है।

सुरक्षा में ये लापरवाही आ चुकी है सामने

पहले दो दिन लगातार डमी आतंकी विस्फोटक लेकर लालकिले के अंदर गए थे। दोनों बार पकड़े नहीं गए

पिछले सप्ताह लालकिले के सामने से अवैध रूप से रह रहे पांच बांग्लादेशी पकड़े गए थे

भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा- मोदी

बेंगलुरु।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया। मोदी ने बेंगलुरु में कहा- भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10 वें नंबर से टॉप 5 में आ गए है।

जल्द ही टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25फीसदी टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। ट्रम्प ने कहा था- भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबें, मुझे क्या। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा- भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने में लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। इसकी सफलता के पीछे हमारी टेक्नॉलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत है। इसमें बेंगलुरु के युवाओं का भी बहुत योगदान है। पीएम कर्नाटक के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। पीएम ने बेंगलुरु और राज्य के लिए कई विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम ने बेंगलुरु मेट्रो की यलो लाइन का भी उद्घाटन किया। जो आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मसंद्रा तक जाएगी।

पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें...

*येलो मेट्रो लाइन के आने लाखों लोगों को फायदा होगा। आज ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया। इसके शुरू होने के बाद यलो और ऑरेंज मेट्रो लाइन से 25 लाख लोगों को फायदा होगा। बेंगलुरु मेट्रो के लिए इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों ने फंडिंग की। इसके लिए कार्पोरेट सेक्टर को बधाई।

*2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे और इनकी संख्या 160 से ज्यादा है। सिर्फ 3 नेशनल वॉटरवेज थे अब ये संख्या 30 हो चुकी है। 11 साल पहले 7 एम्स थे, अब 22 एम्स और 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर था। आज 824 बिलियन डॉलर है।

*इंडिया ग्लोबल एआई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन की स्पीड पकड़ रहा है। जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रहा है। भविष्य से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है।

*पहले मोबाइल इम्पोर्ट करते थे आज टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए है। बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 बिलियन डॉलर था जो अब 38 बिलियन डॉलर हो गया है। ऑटो मोबाइल एक्सपोर्ट 16 बिलियन डॉलर था जो अब डबल हो चुका है।

*सही रिफॉर्म्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने कानून डिक्रिमिनाइल्ज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया जल्द ही 2.0 भी पास करेंगे। राज्य सरकार को भी ऐसे बिल पास करना चाहिए।

तीन वंदे भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी
पीएम मोदी ने बेंगलुरु को दी नई मेट्रो लाइन की सौगात

प्रधानमंत्री ने जिन तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई उनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं.

कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं, भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं- राजनाथ

रक्षा मंत्री का ट्रंप पर का तीखा हमला

नई दिल्ली।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे 'दबंग और गतिशील' अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि 'सबके बॉस तो हम हैं' का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है. राजनाथ सिंह ने ट्रंप पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि कुछ बॉस भारत की तेज विकास दर से जलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, कुछ लोग भारत की तेज प्रगति से खुश नहीं हैं. उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है. 'सबके बॉस तो हम हैं', तो भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है?

अमेरिका का भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 25फीसदी शुल्क और अतिरिक्त 25 फीसदी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख रहा है. यह कदम वॉशिंगटन द्वारा इस आरोप के बाद उठाया गया कि भारत, रूस के युद्ध प्रयासों को वित्तपोषित कर रहा है. इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया और आगे शुल्क बढ़ाने की धमकी भी दी थी.

भारत की अर्थव्यवस्था रोकने की कोशिश

राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ देश चाहते हैं कि भारत में बने उत्पाद, भारतीय हाथों से तैयार चीजें, बाकी देशों की तुलना में महंगी हो जाएं, ताकि दाम बढ़ने पर दुनिया उन्हें खरीदना बंद कर दे. उन्होंने भरोसा जताया कि अब दुनिया की कोई ताकत भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती.

रक्षा निर्यात में मजबूती

रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र को भारत की मजबूती का उदाहरण बताते हुए कहा, हम 24,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं. यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात लगातार बढ़ रहा है.÷ उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ विवाद का इस क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है.

वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का नया अभियान, वेबसाइट लॉन्च कर जनता से मांगा समर्थन

- चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला नया मोर्चा
- चुनाव आयोग के खिलाफ आर-पार के मूड में राहुल गांधी

नई दिल्ली।

फर्जी मतदाता मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाते हुए कहा कि वो नियमों के अनुसार स्पष्ट घोषणा और शपथ पत्र प्रस्तुत करें या फिर अपने झूठे और भ्रामक आरोपों के लिए देश से सार्वजनिक माफी मांगें. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष ने अब इसके खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि मानो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से दो-दो हाथ करने की ठान ली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार (10 अगस्त, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वोट चोरी 'एक व्यक्ति, एक वोट' के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है. राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें. उन्होंने आगे कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें - http://votechori.in/ecdemand पर जाएं या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें. ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है. राहुल गांधी ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. इन पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव के मामले का जिक्र किया, जबकि इस मामले में 2018 में ही कार्रवाई हो चुकी है.

चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है. आयोग ने साफ किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए नेताओं को तथ्यों और सबूतों के साथ ही बयान देने चाहिए.

पीएम मोदी ने कर्नाटक का रेल बजट बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये किया- रेल मंत्री अश्विनी

बंगलुरू।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कर्नाटक का रेल बजट 2014 से पहले के 835 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,500 करोड़ रुपये हो गया है। वैष्णव ने कहा कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पिछले 11 वर्षों में बिजली जैसा विकास देखा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंगलूरू मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाने के बाद कार्यक्रम में बोलते हुए वैष्णव ने कहा, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्य को 2014 से पहले केवल 835 करोड़ रुपये मिलते थे। मोदी की बदौलत अब उसे 7,500 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 54,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। हम अमृत भारत योजना के तहत राज्य में 61 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले 11 वर्षों में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़ा है और उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसी अवधि में निर्यात आठ गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा, ग्यारह साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से कर्नाटक सहित पूरे देश को लाभ हुआ है। वैष्णव ने कहा, अगर भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, तो नम्मा बंगलूरू में देवनहल्ली एक प्रमुख आईफोन निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा, इसीलिए हमारे पास भारत एआई मिशन है, जिसके तहत हमारे सभी नवप्रवर्तकों के लिए एक साझा कंप्यूटिंग सुविधा के रूप में 34,000 जीपीयू उपलब्ध हैं। मुझे पता है कि बंगलूरू इसका अधिकतम उपयोग कर रहा है। इन जीपीयू के उपयोग की लागत 1 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे से भी कम है, जो इसे दुनिया की सबसे किफायती साझा कंप्यूटिंग सुविधा बनाता है।

डबल वोटर आईडी विवाद

तेजस्वी के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम विजय कुमार

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा उन पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप लगाए जाने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिन्हा पर दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से दो वोटर आईडी होने का आरोप लगाया था और इसके सबूत भी पेश किए थे।

तेजस्वी यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये लोग संविधान को नहीं मानते और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि हर चुनाव से पहले यह प्रक्रिया होती है। सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल नहीं खेलती, बल्कि लोकतंत्र के हित में काम करती है और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, विजय सिन्हा न तो उम्र की धोखाधड़ी करते हैं और न ही संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं।

तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि विजय कुमार सिन्हा के पास दो वोटर आईडी है। एक वोटर आईडी में उनकी उम्र 57 साल बताई गई है, जबकि दूसरे में 60 साल। उन्होंने कहा कि यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट और नई मतदाता सूची में भी उपलब्ध है। यादव ने कहा, केवल दो ही बातें हो सकती हैं- या तो चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया ही फर्जी है या फिर बिहार के उपमुख्यमंत्री फर्जी है।

झज्जर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.1 रही तीव्रता, लोगों में दहशत

झज्जर। हरियाणा के झज्जर जिले में रविवार, 10 अगस्त को दोपहर 4 बजकर 10 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि की है कि इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तिव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप की गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी। बीड सुनारवाला गांव भूकंप का केंद्र रहा।

गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करेगी राज्य सरकार : सीएम योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज कराने में उनकी पूरी मदद करेगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं, सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी, उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। योगी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनकी अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। उन्होंने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और पारिवारिक मामलों के निस्तारण में दोनों पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए। एक महिला की गुहार पर उन्होंने अफसरों को उक्त महिला को जमीन का पट्टा देने का निर्देश दिया।

5 लाख का वादा, 5 हजार की थमाई मदद, उत्तरकाशी में फूटा पीड़ित परिवारों का गुस्सा

देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई अचानक बाढ़ के बाद, धराली गांव के लोगों ने सरकार से मिली 5,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि को लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इस भयंकर आपदा में हुए भारी नुकसान को देखते हुए यह राशि नाकाफी है। धराली और हर्षिल के बाद प्रभावित परिवारों को यह सहायता तत्काल राहत के तौर पर दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर उनके नुकसान को कम आंकने का आरोप लगाया है। इस मामले में, उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि 5,000 रुपये की यह राशि सिर्फ एक शुरुआती मदद है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नुकसान का पूरा आकलन होने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने के बाद, प्रभावितों को सही मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन परिवारों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसके अलावा, आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को भी इतनी ही राशि दी जाएगी। सरकार ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति बनाई है, जो पुनर्वास और आजीविका की बहाली के लिए एक योजना तैयार करेगी। इसकी शुरुआती रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर सौंप दी जाएगी। इस बीच, बचाव कार्य पांचवें दिन भी जारी रहा। हेलीकॉप्टरों से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दूरदराज के इलाकों में खाने के पैकेट पहुंचाए गए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने डॉग स्क्वॉड और थर्मल इमेजिंग उपकरणों की मदद से धराली बाजार में मलबा हटाने का काम किया, जहां मंगलवार को भूस्खलन के कारण कई होटल, होमस्टे और दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं।

बिजनौर में तीन भाइयों की मौत, पंपिंग सेट का पट्टा ठीक करने कुएं में उतरे थे, जहरीली गैस से घुट गया दम

बिजनौर। पंपिंग सेट का पट्टा चढ़ाने के लिए कुएं में उतरे तीन भाइयों की मौत हो गई। मोटर कुएं के ऊपर रखी हुई थी, जबकि पंप नीचे नीचे था। पंप से पट्टा उतरा तो एक-एक कर तीनों भाई चढ़ाने के लिए नीचे उतर गए। कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से दम घुटकर उनकी मौत हो गई। रविवार को ग्राम सरकथल निवासी छत्रपाल सिंह (25), अपने चचेरे भाई हिमांशु और सगे भाई कशिश उर्फ छोटू के साथ ट्यूबवेल पर गया था। छत्रपाल मोटर का पट्टा चढ़ाने के लिए कुएं में उतरा था। लगभग 20 फीट गहरे कुएं में नीचे पहुंचा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके तुरंत बाद हिमांशु व कशिश उर्फ छोटू एक-एक कर नीचे उतरे और बेहोश होकर गिर गए। वहां मौजूद धर्मवीर सिंह ने शोर मचा दिया, जिससे वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। भीड़ में शामिल गांव का ही चेतन साहस कर मुंह पर भीगा हुआ कपड़ा लपेटकर कुएं में उतरा और किसी तरह से तीनों को रस्सी में बांधा। इसके बाद भीड़ ने रस्सी के सहारे तीनों को बाहर निकाल लिया। तीनों भाइयों को इलाज के लिए सीएचसी नूरपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीन भाइयों की मौत पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विजय सिन्हा को इस्तीफा देना चाहिए, राजेश राम बोले- बीजेपी के नियंत्रण में है चुनाव आयोग

पटना। दो ईपिक कार्ड और दो जगह मतदाता सूची में नाम मिलने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के नाम दो जगह है। पहला बांकीपुर और दूसरा लखीसराय विधानसभा में। उनका यह डिटेल हलफनामे में दर्ज होगा। अब वे बताये को वह जिस संवैधानिक पद पर बैठे है, क्या वह उससे इस्तीफा देंगे। राजेश राम रविवार को सदाकत आश्रम में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिन्हा कह रहे है कि उन्होंने सुधार करने के लिए दिया है, मगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है की विपक्ष आज तक आयोग की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाता रहा है वह सही है। क्योंकि, चुनाव आयोग उनकी भी नहीं सुन रहा है। अगर उनका नाम दो जगह हलफनामे में है, तो यह एक अपराधिक घटना है। यह पूरी करामात भाजपा के लोग मिलकर कर रहे है। आप कह रहे है कि आपने नाम हटाने के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन किसी कारणवश नाम नहीं हटाया गया। फिर दोनों जगह से एसआईआर फॉर्म क्यों भरा? दोनों जगह फॉर्म पर हस्ताक्षर क्यों किए? अगर पटना में नाम हटाने के लिए आवेदन दिए हैं, तो फिर फॉर्म प्रमाणपत्र सहित क्यों भरा? आपका नाम पटना में ड्राफ्ट के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, जबकि लखीसराय में प्रमाणपत्र के लिए प्रतीक्षा चल रही है, यह कैसे हो गया? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा चुनाव आयोग भाजपा के कब्जे में है। उन्होंने कहा सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो जवाब भाजपा देती है। जो लोग बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहते है और उसपर जीतकर आए है, तो उन्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। सरकार में बैठे लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने तो महाराष्ट्र का बताया था लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का दो जगह नाम है। यहां वोट चोरी नहीं होती तो आज केंद्र में सरकार नहीं बनती। केंद्र में बैठे लोगों की दो बैसाखी है, एक बिहार में नीतीश कुमार और दूसरे चंद्र बाबू नायडू। प्रेस कांफ्रेंस में प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राठौड़, सौरभ सिन्हा व अन्य नेता उपस्थित रहे।